

**Title:** Urged upon the Government to apply Article 355 of the Constitution to restore peace in Gujarat.

**श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) :** उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के सवाल पर इस सदन में 11 मार्च को नियम 193 के अधीन चर्चा हुई, 30 अप्रैल को नियम 184 के तहत इस पर चर्चा हुई और अभी राज्य सभा में नियम 170 के अधीन इस पर चर्चा हो रही है। उस चर्चा में भारत के विदेश मंत्री और उस सदन के नेता श्री जसवंत सिंह ने कहा था कि सरकार प्रस्ताव की मूल भावना के साथ है और संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत सरकार कार्यवाही करेगी। कल ग्वालियर में पत्रकारों से बात करते हुए भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि गुजरात में अनुच्छेद 355 के तहत कार्यवाही किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बहुत गंभीर मामला है। (व्यवधान) गुजरात में एक दिन भी खून-खराबा नहीं रुका है। कल भी वहां सात लोग मारे गए हैं। यह अत्यधिक गंभीर मामला है। जिस दिन गोधरा की घटना हुई, उसके तत्काल बाद सरकार यह प्रचार करती रही कि यह घटना पूर्व नियोजित थी। रेलवे सुरक्षा बल के आई.जी. की रिपोर्ट के मुताबिक गोधरा की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। हिन्दुस्तान के गृह मंत्री श्री लाल कृण आडवाणी ने कहा है, जो एशियन एज में छपा है - Advani rejects Modi's riot theory.

**13.00 hrs.**

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है, जान-बूझकर जांच को प्रभावित करने का काम है। राज्य सभा में जो सरकार की तरफ से श्री जसवन्त सिंह ने पक्ष रखा, उसके विपरीत प्रधानमंत्री दूसरी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** रामजीलाल सुमन जी, यह गंभीर मामला है तो भारत सरकार को इस मामले में क्या करना चाहिए, यह कहिये। जीरो ऑवर भाण करने के लिए नहीं है। इस विषय में श्री प्रियरंजन दासमुंशी का एक और नोटिस है, दोनों कहिये कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए।

**श्री रामजीलाल सुमन :** उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार कुछ नहीं करना चाहती। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** इस तरह से आप लोगों का विषय नहीं आयेगा।

**श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल अहमदाबाद में था। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** आपका भी नोटिस है, मैं आपको भी बुलाऊंगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramdas, let him complete. Please do not disturb....(Interruptions)

**श्री रामजीलाल सुमन :** उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार कुछ नहीं करना चाहती। कल प्रमोद महाजन जी ने अपने भाण में कहा है कि दुनिया इधर से उधर हो जाये, लेकिन हम श्री मोदी को नहीं बदलेंगे। हमें रोज गुजरात का सवाल उठाने की कोई दिलचस्पी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार का कोई सकारात्मक रुख नहीं है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और बराबर हिंसा का तांडव जारी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री के जो सुरक्षा सलाहकार मि. गिल गये हैं, उन्होंने वहां जो पुलिस के आला अफसरान से बातचीत की है, उस बातचीत में पुलिस के अफसरान ने बताया कि हम क्या करते, हमें तो निर्देशित किया गया था कि बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के प्रति आपका रवैया नरम होना चाहिए। (व्यवधान) 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में कल छपा है, मैं उसे कोट करना चाहूंगा:

"Senior police officers (व्यवधान) "

**उपाध्यक्ष महोदय :** रामजीलाल सुमन जी, आप बैठिये। यह जीरो ऑवर है।... (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** भारत सरकार इस सिलसिले में क्या कर रही है, यह पूछिये। यह जीरो ऑवर का मामला है, इसे स्पीच बनाएंगे तो क्या होगा। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह महत्वपूर्ण मामला है, आप जरा एक मिनट बैठिये न। मैंने कहा है कि 7-8 मंम्बर हैं, जो हर रोज नोटिस देते हैं, उन लोगों को इश्यू रोज करने का मौका मिलना चाहिए। वह खत्म करके हम हाउस एडजर्न करना चाहते हैं। आप बोलते हैं तो ये सब लोग उठ खड़े होते हैं। तब फिर यहां भी यही होगा। यह जीरो ऑवर है..... (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** सुनिये, आप बैठिये। रघुवंश जी, बैठिये। इसी सिलसिले में श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने भी नोटिस दिया है।... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him conclude now....(Interruptions)

**श्री रामजीलाल सुमन :** मैं दो मिनट लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कल 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपा था, वहां के आला पुलिस अफसरान ने जो कहा है, उसे मैं कोट करना चाहता हूं:

"We were told to go slow, Gujarat cops tell K.P.S. Gill : Senior police officers with whom K.P.S. Gill held a series of meetings on Saturday are learnt to have told the former Punjab police chief that law and order machinery had collapsed in the State because they were given clear instructions to go soft on Bajrang Dal and Vishwa Hindu Parishad activists."

उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा नहीं तो और क्या थी? यह बहुत गंभीर सवाल है. दो महीने से ज्यादा हो गये, देश की सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है और श्री नरेन्द्र मोदी को हटाया नहीं जा रहा तो आखिर क्या किया जाये? जो लोग हैं, उनका विश्वास टूटा है। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में छपा है:

"You can come back to your homes only if you (व्यवधान) drop rape charge, convert to Hinduism (व्यवधान). villagers in Gujarat are setting terms for Muslims to return. "

उपाध्यक्ष महोदय, हम क्या करें, कहां जायें? इस सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह एक्शन ले। अगर वहां खून-खराबा होगा, राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा होगी और हम

लोग यहां बात भी न करें तो यह कैसे सम्भव है। दंगा गुजरात की राज्य सरकार ने कराया और जब तक नरेन्द्र मोदी को वहां से नहीं हटाया जायेगा, तब तक वहां स्थिति किसी भी कीमत पर सामान्य नहीं हो सकती।

प्रधान मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उससे साफ है कि प्रधान मंत्री जी की नीयत गुजरात में मोदी को हटाने की नहीं है। वे नहीं चाहते कि गुजरात में स्थिति सामान्य रहे। (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Priya Ranjan Dasmunsi has given a notice. Shri Ramdas Athawale, please sit down.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Deputy-Speaker, Sir, through you, I would like to draw the attention of the Government to the following matter.

Sir, in this House, we all debated the issue of Gujarat and, without any political acrimony, we all desired that peace must prevail in Gujarat. People of all sections in Gujarat must, once again, revel in being Gujaratis and being Indians. I am not here to score any political points against any party. The situation in Gujarat has very well been explained by all sections of the House the other day, and the debate is now on in the other House.

I would only like to place one matter before you. The hon. Prime Minister, in this very House, made an appeal to bring back peace in Gujarat, and also assured all of us that he would act firmly. The Hon. Home Minister, Shri Advani, equally echoed it. We discussed the Gujarat issue under a lighter Motion. I do not know the reason, and I am not competent to question that, but we came to know through the newspapers -- neither am I sure about the proceedings, nor am I competent to quote the proceedings of the other House -- that the Government, in principle, has accepted that the situation in Gujarat is such that the provision of article 355 applies. Article 355 is a provision which puts the complete obligation on the Government to take the responsibility of ensuring peace, tranquillity in a State, here, in this case, the State of Gujarat.

Having accepted that in principle, no less than our Prime Minister and the Leader of the House, to whom we all look to, made it known in Gwalior, and I am quoting from the *Asian Age*, "Vajpayee told reporters on Saturday night that although there was a provision to issue a notice to a State Government under article 355 of the Constitution, this was not needed in the case of Gujarat where the State Government was doing reasonably well." I think, this very statement is not only an assault on the Constitution, but also shows the casual nature of treating the collective wisdom of this House, which unequivocally appealed, including the NDA partners, that cognizance should be taken of the happenings in Gujarat and efforts should be made to bring back normalcy. The Prime Minister feels that though the provision is there, there is no requirement to give any notice. The Shahpura incident, the incidents taking place one after the other in various parts are creating such a situation, I feel that the Prime Minister should not have said that or expressed his own view, ignoring the provision of the Constitution.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I will not take any more time. I only appeal, through you, Sir, that political parties may score their points outside the Parliament. However, is it fair to bring down the stature of Sardar Vallabh Bhai Patel, the Iron Man of the country, the great patriot of the country, and the secular leader of the Nation? In Gujarat, a chorus is going on that Narendra Modi should be treated as the *Bada Sardar*. It is another attempt at diluting the stature of our national leaders. This should not be encouraged. I think, the Government, on its own, should condemn such method of equating Sardar Vallabh Bhai Patel with Narendra Modi.

Sir, in the *Ramayana*, when Lord Rama, the *Maryada Purushotham*, comes back after conquering Lanka, a *dhobi* points out, "Lord Rama, I praise you. You are my God. You are ruling Ayodhya in true sense of the term 'democratic'. I may be a *dhobi*, but I have a doubt on great Sita *maiyya*." After hearing this, Lord Rama said: "Since you have a doubt, I ask Sita to go to a separate place and prove herself." When people question the *bona fides* of Modi -- when Lord Rama could do that to Sita -- can Shri Vajpayee not ask Modi to get out, if they are true followers of Shri Ramachandra? ...(*Interruptions*)

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): Do you believe in Lord Rama?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Therefore, I appeal through you, Sir, that the Prime Minister should take immediate cognizance of the fact, apply article 355, give the notice and give specific direction as to how the things should be restored to normalcy. This is my appeal, through you, Sir, to the Government and I expect an appropriate reaction from it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, except Shri Prahlad Singh Patel, there are three other Members who have given notice on this recent crash of Mig-21. They are, Shri Sahib Singh Verma, Shri Ramdas Athwale and Shri Jagmeet Singh Brar.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I also have given a notice.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your notice is there. I will call your name. We would finish the list today.